पुराने आंकड़े, जंग लगे पैमाने

हरिकिशन शर्मा

बीच बहस में

राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी 24 जुलाई को 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात का जायजा लेंगे कि समावेशी विकास का सपना संजोकर चली यह योजना अब तक कितनी सफल रही। क्या यह विकास के पथ पर सभी समुदाय और क्षेत्रों के लोगों को साथ लेकर चलने में कामयाब रही है?

सुनने में ये बातें रोचक लग सकती हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या योजना आयोग का पैमाना सवा तीन साल के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाएगा? जवाब है नहीं। क्योंकि योजना आयोग जिस पैमाने पर मध्यावधि समीक्षा कर रहा है, उसे अब जंग लग चुकी है। आर्थिक विकास के संकेतक मसलन, आर्थिक वृद्धि दर, निवेश दर, बचत दर, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि को छोड़ दें, तो सामाजिक या मानव विकास की प्रगति दिखाने का एक भी कारगर संकेतक इसके पास मौजूद नहीं है। सामाजिक और मानव विकास का जायजा लेने के लिए वह आज भी दशकों पुराने तरीकों और वर्षों पुराने आंकड़ों पर निर्भर है। ये आंकड़े भी उसके अपने नहीं हैं। अलग-अलग संस्थाओं के हैं। इनकी विश्वसनीयता पर भी बहस हो सकती है। फिलहाल तो हम इनके अपडेट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या तीन साल पुराने आंकड़ों से पिछले तीन साल के प्रदर्शन का मूल्यांकन हो सकता है?

एनडीसी की बैठक से ठीक हफ्ते भर पहले पत्रकारों से रूबरू हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि गिनाने के लिए आर्थिक विकास दर का राग अलाप रहे थे। उनका कहना है कि योजनावधि में औसतन 8.1 फीसदी से अधिक विकास दर रहेगी, जो नौ फीसदी के लक्ष्य से कम, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले अधिक है। उनके लिए विकास का मतलब महज आर्थिक वृद्धि दर रह गया है। लगता है, जीवन के बाकी पहलू उनकी नजरों से ओझल हो गए हैं। और पंचवर्षीय योजना के बाकी लक्ष्य भी। यही वजह है कि अहलूवालिया आजकल कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश को अब बीमारू कहना उचित नहीं है। लेकिन यूपी, बिहार में अशिक्षा, गरीबी और प्रसव के दौरान दम तोड़ती महिलाओं की संख्या उन्हें नजर नहीं आती। आए भी कैसे? उनके पास इनके आंकड़े ही नहीं हैं। पूछिए, तो तीन साल पुराने आंकड़े सुना देंगे।

11वीं पंचवर्षीय योजना के बाकी लक्ष्यों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी शामिल थीं। लेकिन आयोग ने इनके मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर आंकड़े जुटाने का बंदोबस्त ही नहीं किया। इनके लिए वह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण और जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों पर निर्भर है, जो काफी पुराने हैं। कुछ का आधार वर्ष तो योजना के शुरू होने से भी पहले का है। मध्यावधि समीक्षा भी इन्हीं के आधार पर हो रही है। जिन आंकड़ों पर आयोग भरोसा कर रहा है, वे अधूरे भी हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज फेलोशिप- 2010 के तहत हमने शिशु-मातृ मृत्यु दर के आंकड़े जुटाने की सरकारी प्रक्रिया जानने के लिए राजधानी से महज 50 मील दूर हरियाणा के मेवात जिले का दौरा किया। सरकारी मुलाजिम किस तरह आंकड़े इकट्ठा करते हैं, इसका एक नमूना हमने वहां देखा। योजना आयोग की एक टीम ने इस जिले का दौरा कर दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी। इसके मुताबिक, मेवात में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 75 मौत की है। लेकिन जब हमने जिले के सीएमओ से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने एक सर्वे का हवाला देकर हमें प्रति हजार 80 शिशु से अधिक बताई। हमारे अनुमान के हिसाब से यह संख्या और भी अधिक हो सकती है।

आप इन तथ्यों पर गौर कीजिए। सचाई सामने आ जाएगी। क्या हमारे देश में बच्चों के जन्म और मृत्यु का 100 फीसदी पंजीकरण होता है? जाहिर है, ऐसा नहीं होता। तो फिर शिशु मृत्यु दर की सही तसवीर कहां से सामने आएगी? साफ है, मानव विकास की स्थिति का सही अंदाजा लगाने के लिए आयोग के पास कोई संस्थागत ढांचा मौजूद नहीं है। क्या एनडीसी इस दिशा में कोई पहल करेगी?